



Neutral Citation-2026: AHC:20566

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 3025 / 2026

राय साहब और अन्ययाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार तिवारी

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या T202314360605470 (राय साहब और अन्य बनाम अमरनाथ) का शीघ्रता से निपटारा करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि उ.प्र. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, उ.प्र. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त होगा। यह उप-नियम अनिवार्य करता है कि ऐसे किसी आवेदन के दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, एक समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा करना आवश्यक होगा। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर दाखिला खारिज के निर्विवाद मामले को और 90 दिनों की अवधि के भीतर दाखिला खारिज के विवादित मामले को निपटाने का प्रयास करेगा; और यदि ऐसी अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और उसका निपटारा, कानून के अनुसार, पूरी तरह से उसके अपने गुण दोष के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से करें। यह निपटारा, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से, अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए; बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो, और इस प्रक्रिया में अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने, विरोधी पक्षों की दलीलों के गुण दोष के संबंध में, कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडेया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"